1	2	3
पंजाब एण्ड सिंध बैंक	12.04	10.84
पंजाब नेशनल बैंक	10.38	9.57
सिंडिकेट बैंक	7.53	5.78
यूको बैंक	13.73	11.14
यूनियन बैंक आफ इंडिया	6.98	7.66
युनाइटेड बैंक आफ इंडिया	18.70	12.10
विजया बैंक	9.56	7.40

(*) अनंतिम।

आधारभूत सुविधाओं के लिए वांछित धनराशि

4502. **श्री बरजिन्दर सिंह:**
श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने, देश में आधारभूत मूल सुविधाओं के बनाने के लिए योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु अगले पांच वर्षों में वांछित धनराशि का आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो कुल कितनी वांछित धनराशि का अनुमान लगाया है; और

(ग) विद्युत, संचार, इस्पात, पैट्रोलियम, सड़कों, रेल और कोयले आदि के क्षेत्र में आवश्यकता का कुल कितना अनुमान है?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा): (क) और (ख) वित्त मंत्रालय द्वारा अक्टूबर, 1994 में गठित आधारभूत ढांचा परियोजनाओं के वाणिज्यिकरण संबंधी विशेषज्ञ दल ने जून, 1996 में सरकार को प्रस्तुत "इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर रिपोर्ट" में आधारभूत ढांचा क्षेत्रकों अर्थात् विद्युत, सड़कें, पत्तन, दूरसंचार और शहरी आधारभूत ढांचे के लिए निवेश आवश्यकताओं का अनुमान लगाया है। विशेषज्ञ दल के अनुसार आधारभूत ढांचा क्षेत्र में कुल निवेश सकल घरेलू उत्पाद का 5.5 प्रतिशत के वर्तमान स्तर से बढ़कर वर्ष 2000-01 तक सकल घरेलू उत्पाद का 7 प्रतिशत होने की आशा है। समग्र रूप में यह वार्षिक निवेश में 600 बिलियन रु० से वर्ष 2000-01 तक लगभग 1100 बिलियन रु० की वृद्धि को इंगित करता है। इस अवधि के दौरान (1996-97 से 2000-01) किए जाने वाले कुल निवेश के रूप में अनुमान 4000-4, 500 बिलियन रु० बैठते हैं।

(ग) विशेषज्ञ समूह ने आधारभूत ढांचे के क्षेत्रवार निवेश का भी अनुमान लगाया है, ये इस प्रकार है:—

क्षेत्रक	1996-97 से 2000-01 (बिलियन रु०)
विद्युत	1834
दूर संचार	740
सड़क	320
पत्तन	100
शहरी आधारभूत ढांचा	800-940

सरकार द्वारा उधार लिया जाना

4503. **श्री बरजिन्दर सिंह:**
श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार, जून, 1998 के अन्त तक विभिन्न माध्यमों से 79,000 करोड़ रुपये उधार ले चुकी है;

(ख) यदि हां, तो उधार ली हुई सही राशि क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि सरकार द्वारा भारी मात्रा में उधार लेने से अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने के अवसरों में वृद्धि हो रही है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और क्या सरकार उधार लेने की कोई सीमा निर्धारित करने का विचार करेगी और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा): (क) से (घ) कुल व्यय और ऋण-भिन्न प्राप्तियों (राजकोषीय घाटा) के बीच अन्तर को पूरा करने के लिए सरकार को सभी स्रोतों से आवश्यक कुल उधार राशि चालू वर्ष 1998-99 के बजट अनुमानों में 91025 करोड़ रुपए आंकी गई है। जून अंत, 1998 के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। किसी भी तरह एक वर्ष की मध्यावधि के आंकड़े वर्षान्त की स्थिति प्रतिबिम्बित नहीं करते।

सरकार ऋण-भिन्न प्राप्तियों को अधिक से अधिक बढ़ाकर तथा व्यय को नियंत्रित करते हुए चालू वर्ष में राजकोषीय घाटे की बजटीय स्तर पर रोके रखने का प्रयास करेगी।